



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, २९ अप्रैल, १९९५/९ वंशाख, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, १८ अप्रैल, १९९५

संख्या एल० एस० जी०डी (१) २/८४-III.—खण्डाघाट (श्रीनगर) का क्षेत्र, जो उस समय शिमला जिला की क्षेत्रीय अधिकारिता में था, को ईस्ट पंजाब अर्बन रेन्ट रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट, १९४९ की धारा २ के खण्ड (जे) के अधीन पंजाब सरकार के राजपत्र तारीख ९-७-१९६५ में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ५६९५-आई. सी० आई-६५-२३००८, तारीख २९-६-१९६५ द्वारा नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया था।

तत्पश्चात् ईस्ट पंजाब अर्बन रेन्ट रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट, १९४९ को दो हिमाचल प्रदेश अर्बन रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट, १९७१ द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जबकि उक्त अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी अन्य न्यायालय या अथवा प्राधिकारी के समक्ष सभी वाद और अन्य सभी कार्यवाहियाँ सुरक्षित रखी और निरस्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटाए जाएँगे। दो हिमाचल प्रदेश रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट, १९७१ को भी हिमाचल प्रदेश विन्यास नियन्त्रण अधिनियम, १९८७ द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल साधारण खण्ड अधिनियम, १९६८ की धारा २० के साथ पठित हिमाचल प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना को तुरन्त प्रभार से विखंडित करते हैं। परन्तु यथास्थिति उक्त निरस्त अधिनियमों या हिमाचल प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९८७ के अधीन विभिन्न न्यायालयों और प्राधिकरणों में, यदि कोई हो, जो उक्त क्षेत्र पर अधिकारिता रखते हों' में संस्थित मामले यथास्थिति उक्त

निराश्रित अधिनियमों या हिमाचल प्रदेश किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 के उपबन्धों के अनुसार निपटारा जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of this Department notification No. LSG-D (1)-2/84-III, dated 18-4-1995 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th April, 1995

No. LSG-D (1)-2/84-III - Whereas the area of Kandaghat (Sirinagar) which was under the territorial jurisdiction of Shimla district at that time, was declared as urban area under clause (j) of section 2 of the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 vide notification No. 5695-ICI-65-230 8, dated 29-6-1965 and published in the Punjab Government Gazette dated 9-7-1965.

Whereas thereafter the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949, was repealed by the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1971, while all suits and other proceedings under said Act, pending at the commencement of this Act, before any Court or other authority were saved and to be disposed off in accordance with the provisions of repealed Act. The Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1971 has also been repealed by the Himachal Pradesh Rent Control Act, 1987.

Now, in exercise of the powers conferred by clause (k) of section 2 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 read with section 29 of the Himachal Pradesh General clauses Act, 1968, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to rescind the said notification with immediate effect. Provided that the areas institution under the said repealed Acts or the Himachal Pradesh Rent Control Act, 1987 as the case may be in various courts and other authorities if any, having jurisdiction over said area shall be disposed off in accordance with the provisions of the said repealed Acts, or the Himachal Pradesh Rent Control Act, 1987, as the case may be.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.